अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): उपसभापति महोदय, ऑनरेबल मेम्बर ने जो इश्यू उठाया है, वह भावनात्मक रूप से न केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं कंसर्न्ड मिनिस्टर को इसके बारे में बताऊंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is correct.

Hardships being faced by drivers of App-based taxi aggregators

श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस विषय को उठाने के लिए मौका दिया है। सर, यह विषय सिर्फ टैक्सी ड्राइवर्स का नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी का भी विषय है। टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बनती है, लेकिन इंसान टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बनता है। मैं अभी रीसेंटली कोलकाता में उबर टैक्सी से अपने घर से एयरपोर्ट जा रहा था। मैं जिस टैक्सी से जा रहा था, उस टैक्सी का ड्राइवर बहुत दुखी था। उसने रास्ते में बात करते-करते बताया कि उबर ने अपने रेट कम कर दिए हैं और ओला ने भी अपने रेट कम कर दिए हैं। दोनों में बहुत competition हुआ, इस चक्कर में उबर अपने ड्राइवर को मोबाइल के लिए जो पैसा देती थी, वह देना बंद कर दिया। उबर इनसे कमीशन के तौर पर जो चार्ज करती है, उसको भी बढ़ा दिया। इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं, जो वह अपने ड्राइवर्स को देती थीं, उनको बंद कर दिया। उबर और ओला कमर्शियल कपनियां हैं, वे जो चाहें, कर सकती हैं, मगर क्या हम लोग इसको आंख बंद करके देखते रहेंगे? क्या सरकार इस पर कोई नियंत्रण नहीं करना चाहेगी, कोई रेग्युलेशन नहीं करना चाहेगी? सर, मजे की बात यह है कि ये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो उबर और ओला के तहत काम करते हैं, ये अपनी बात को लेकर किसी दफ्तर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उबर और ओला का इंडिया में कोई दफ्तर ही नहीं है। अब वे Government के किस Department के पास शिकायत करने के लिए जाएं? Government भी शिकायत सुनने के लिए सामने नहीं आती है। उबर और ओला के जो ड्राइवर्स हैं, इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कोई कोर्ट उन्हें entertain नहीं करता और Government भी उन्हें support नहीं कर रही है। यह problem आज भले ही छोटी दिखाई दे रही है लेकिन अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले, दिल्ली, बेंगलुरु आदि सब जगह उबर और ओला के drivers strike पर चले गए थे, जिससे सब जगह taxies की बहुत shortage हो गई थी। हमारे जैसे कई लोग आज भी taxi का उपयोग airport और station आने-जाने के लिए करते हैं। इस situation पर अगर जल्दी नियंत्रण नहीं पाया गया तो यह बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। उसका कारण है कि इन drivers ने अपनी गाड़ियां एक-दो साल पहले उबर या ओला के साथ 5 साल का agreement करने के बाद खरीदी थीं। एक-एक taxi driver का लगभग 40 हजार रुपए महीने का खर्चा बंधा हुआ है, जिसमें उनकी किश्त, EMI, Petrol, Diesel और बाकी दूसरे खर्च शामिल हैं। आज उनके सामने ऐसी हालत पैदा हो गई है कि अगर 20 घंटे भी एक driver दिन में काम करेगा तो भी वह प्रतिमाह 40 हजार रुपए नहीं कमा सकता। उसे उधार लेकर अपना जीवन-यापन करना पड़ रहा है। जब वह उधार नहीं चुका पाएगा तो बहुत जल्द suicide करने पहुंच जाएगा। यदि बाद में हम जागें, उससे अच्छा है कि हम लोग आज ही जाग जाएं और इस मामले में कुछ-न-कुछ कार्यवाही करें। Government भी इन

लोगों को चूसने पर लगी हुई है क्योंकि Airport पर सरकार ने इन पर 150 रुपये का parking charges भी लगा दिया, जितनी बार ये लोग airport जाते हैं। इनका जो commission बढ़ाया गया है, वह सरकार की knowledge में ही या नहीं, मुझे नहीं पता कि सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है लेकिन मैं आपके जरिए मंत्री जी से request करना चाहता हूं कि इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण दें और इन लोगों की जो भी तकलीफें हैं, उनसे इन्हें निजात दिलाएं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Shri B.K. Hariprasad. ...*(Interruptions)*...

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं इस विषय के साथ अपने आपको संबद्ध करता हूं।

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक): महोदय, मैं इस इस विषय के साथ अपने आपको संबद्ध करता हूं।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, it is a very serious issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sometime it will explode. Now the indication has already been seen. A big number of workers who are keeping our transport system on are being squeezed, squeezed and squeezed, and ultimately it will explode. I think, the Government must take note of it, those who are taking care of the transport system, they must respond. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. The Government will take note of it. ...*(Interruptions)*... The Government will take note of it. Okay.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): माननीय सदस्य ने प्राइवेट taxi services के बारे में जो मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है कि कुछ private taxi services अच्छा काम भी कर रही हैं,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Convey it.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: लेकिन जो तमाम तरह की technology है और technology के बाद, उसके जो तमाम तरह के experiences होते हैं, ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do something. Okay. ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: फिर भी माननीय सदस्य ने जो concern व्यक्त किया है, उसे मैं संबंधित मंत्री की जानकारी में ला दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shri B.K. Hariprasad. ...*(Interruptions)*...

श्री तपन कुमार सेनः कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, वह serious nature का है। **...(व्यवधान)...**

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश)**:** आश्वासन से कुछ नहीं होगा। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः तपन जी बैठिए। Now Shri B.K. Hariprasad. *...(Interruptions)...*

SHRI TAPAN KUMAR SEN: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri B.K. Hariprasad. *...(Interruptions)...* Please start. *...(Interruptions)...* Please start. Only what Shri B.K. Hariprasad is saying will go on record.

Drought situation in Karnataka

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I would like to draw the attention of the Government towards the serious drought situation in Karnataka.

Karnataka is reeling under a serious drought situation. This is the sixth consecutive year right from 2011 to 2016. It has seriously affected both the farmers and the livestock. Sir, this is the second year in succession where both Kharif and Rabi crops have failed due to the severe drought. The State had declared 139 talukas out of 176 talukas as drought-affected. A memorandum seeking financial assistance to the tune of ₹ 4,702 crores as per the SDRF and NDRF norms was submitted to the Government of India on 15-11-2016. Sir, the high-level committee has approved the release of ₹ 1,782 crores, which is yet to be released.

The north-east monsoon has completely failed in Karnataka. The State has recorded only 54 mm of rainfall against the 188 mm of rainfall. There is a deficiency of minus 71 per cent, which is the lowest in the past 45 years. After analysing the seasonal condition as per the Government of India norms, 160 taluks out of 176 taluks have been declared as drought-affected during the Rabi 2016.

Sir, during the Rabi season, an area of 25.98 lakh hectares was sown against the target of 32.25 lakh and 6.2 lakh hectares was left unsown. The estimated loss due to agriculture and horticulture crops is ₹ 7,097 crores in 13.65 lakh hectares. The agriculture and horticulture crop loss due to drought for both Kharif and Rabi put together totals to a staggering ₹ 25,000 crore which has disrupted the farmers' lives and severely affected the socio-economic condition of the State.

*Not recorded.